नईदुनिया

भोपाल, 28 जुलाई 2026

खास-खबरें

आईएएस केशव चंद्र ने संभाला खान सचिव का पदभार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी केशव चंद्र ने सोमवार को भारत सरकार के खान सचिव का पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने से पहले वह नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष (चेयरमैन) के रूप में कार्यरत थे। खान मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, केशव चंद्र अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है, जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का महासचिव नियुक्त किया गया है। पदभार संभालने के तुरंत बाद केशव चंद्र ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं, चल रही गतिविधियों और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उनके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति से विस्तार से अवगत कराया।

मंत्रालय के अनुसार, केशव चंद्र ने देश के खनिज क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए समन्वित प्रयासों और मंत्रालय की प्रमुख पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर लीक

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों की निजी जानकारी तथा बैंक के आंतरिक दस्तावेज डार्क वेब पर लीक होने का मामला सामने आया है। मामले से जुड़े सूत्रों और एक साइबर सुरक्षा शोधकर्ता के अनुसार लीक हुए आंकड़ों में ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, पहचान संबंधी दस्तावेज, ऋण से जुड़े अभिलेख तथा बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षण से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार बैंक ने इस घटना की जांच के लिए फोरेंसिक जांच प्रारंभ कर दी है। हालांकि इस डेटा लीक से कितने ग्राहक प्रभावित हुए हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस संबंध में अब तक शेयर बाजारों को कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि यह घटना बैंक की ईमेल प्रणाली में सेंधमारी के कारण हुई। बताया जा रहा है कि हैकरों ने ईमेल प्रणाली तक पहुंच बनाकर संवेदनशील जानकारी हासिल की। साइबर सुरक्षा शोधकर्ता श्रीकांत एल के अनुसार वेबसाइट के मेटाडेटा विश्लेषण से पता चला कि यह जानकारी शनिवार रात डार्क वेब पर सामने आई, जहां 700 गीगाबाइट से अधिक डेटा उपलब्ध होने का दावा किया गया। इस पूरे मामले पर बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब बड़ी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में संग्रहीत ग्राहकों के आंकड़ों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले जून में एप्पल के आपूर्तिकर्ता टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुए साइबर हमले के बाद कंपनी से जुड़े दस्तावेज डार्क वेब पर सामने आए थे। वहीं, इसी महीने की शुरुआत में 'वर्ल्ड लीक्स' नामक रैनसमवेयर समूह ने भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित फाइलें भी डार्क वेब पर साझा करने का दावा किया था।

इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 21 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी

ओमान को निर्यात में पाँच गुना से अधिक उछाल, अमेरिका बना सबसे बड़ा विदेशी बाजार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अमेरिका, जर्मनी, चीन, सिंगापुर और ओमान जैसे देशों से मजबूत मांग के कारण भारत के इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में जून माह के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद की रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 11.48 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष के इसी माह के 9.51 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है।

परिषद की विज्ञप्ति के अनुसार ओमान को इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात जून में वार्षिक आधार पर पाँच गुना से अधिक बढ़कर 25.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं, चीन को निर्यात 74 प्रतिशत बढ़कर 36.15 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। अमेरिका भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बना रहा, जहां जून के दौरान 1.95 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। जून माह में पश्चिम एशिया के कुछ बाजारों को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख बाजारों में भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं के

निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को निर्यात में कमी रही, फिर भी भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद ओमान को निर्यात में 420 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। इसके कारण पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में कुल मिलाकर इंजीनियरिंग निर्यात की वृद्धि बनी रही। तुर्किये को भी जून में भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष इस बाजार में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई थी।

तीन महीनों से इंजीनियरिंग निर्यात 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर बना हुआ है

रिपोर्ट के अनुसार जून में 34 में से 27 इंजीनियरिंग उत्पाद श्रेणियों में निर्यात बढ़ा, जबकि सात श्रेणियों में गिरावट दर्ज की गई। इनमें सीसा एवं उससे बने उत्पाद, आंतरिक दहन इंजन, स्वचालित नकद निकासी मशीनों की मशीनरी, क्रेन, लिफ्ट एवं विंच, कार्यालय उपकरण तथा प्राइम माइका शामिल हैं। परिषद के अध्यक्ष पंकज चढ्ढा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता और व्यापारिक व्यवधानों के बावजूद भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात क्षेत्र ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है। चालू वित्त वर्ष के लगातार तीन महीनों से इंजीनियरिंग निर्यात 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर बना हुआ है, जो बदलते वैश्विक व्यापारिक वातावरण के अनुरूप उद्योग की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उभरती चुनौतियों पर लगातार नजर रखने और विकास की गति बनाए रखने के लिए सरकार का सहयोग आवश्यक रहेगा।

उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स और गूगल के विरुद्ध दीवानी वाद दायर करने की दी मंजूरी

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से मेरा कोई संबंध नहीं : गडकरी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बंबई उच्च न्यायालय में दायर याचिका में स्पष्ट किया है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम और ई-20 पहल पूरी तरह केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से जुड़े विषय हैं।

याचिका में कहा गया है कि मेटा, एक्स और गूगल जैसे डिजिटल माध्यमों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार किए गए कई भ्रामक वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। इन वीडियो में गडकरी को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम तथा ई-20 पहल से गलत तरीके से जोड़ा गया है। उनका कहना है कि इन वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है।

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को इन डिजिटल सामग्रियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद गडकरी अब मेटा, एक्स और गूगल के विरुद्ध दीवानी वाद दायर कर सकेंगे। याचिका में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा दूरसंचार मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

गडकरी ने न्यायालय में कहा कि इस मुकदमे का उद्देश्य किसी भी सरकारी नीति पर सार्वजनिक चर्चा या आलोचना को रोकना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को सरकारी निर्णयों पर निष्पक्ष बहस और आलोचना का पूरा अधिकार है। उनका कहना है कि आपत्ति केवल उन भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण सामग्रियों से है, जिनमें तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वीडियो तैयार कर यह गलत धारणा फैलाने का प्रयास किया

याचिका के अनुसार अज्ञात व्यक्तियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वीडियो तैयार कर यह गलत धारणा फैलाने का प्रयास किया कि गडकरी और उनके परिवार को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम तथा ई-20 पहल से आर्थिक लाभ हो रहा है। गडकरी ने इन सभी दावों को पूरी तरह निराधार बताया है। उल्लेखनीय है कि देश में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल के मिश्रण वाले ई-20 ईंधन को लेकर कुछ वाहन स्वामियों की ओर से आपत्तियां भी सामने आई हैं। विशेष रूप से वर्ष 2023 से पहले निर्मित पेट्रोल चालित वाहनों के मालिकों का दावा है कि इस ईंधन के उपयोग से वाहनों का औसत कम हो रहा है, रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है तथा इंजन के कुछ पुर्जों के जल्दी खराब होने की आशंका बनी हुई है।

पांच दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में जोरदार वापसी

सेंसेक्स 776 अंक और निफ्टी 228 अंक चढ़ा, सभी प्रमुख क्षेत्रों में रही खरीदारी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह लगातार पांच कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद सोमवार को जोरदार तेजी लौट आई। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक 776.01 अंक यानी 1.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,835.78 अंक पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह इसमें 2,091 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं, राष्ट्रीय शेयर बाजार का निफ्टी-50 सूचकांक भी 228.50 अंक यानी 0.96 प्रतिशत मजबूत होकर 23,995.95 अंक पर पहुंच गया। बीते सप्ताह यह पांच कारोबारी दिनों में 566.85 अंक लुढ़क गया था।

अमेरिका द्वारा शांति वार्ता की संभावना को ध्यान में रखते हुए ईरान पर हमले रोकने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल बना, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दिया। प्रमुख सूचकांकों के साथ-साथ निवेशकों ने व्यापक बाजार में भी खरीदारी की। निफ्टी मध्यम आकार की कंपनियों का सूचकांक 1.28 प्रतिशत तथा लघु आकार की कंपनियों का सूचकांक 1.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान सभी प्रमुख क्षेत्रों में तेजी दर्ज की गई। सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और रियल एस्टेट क्षेत्र के सूचकांक दो प्रतिशत से अधिक मजबूत हुए। इसके अलावा वाहन, दैनिक उपभोक्ता वस्तु, औषधि, स्वास्थ्य तथा रसायन क्षेत्र के सूचकांकों में भी एक से दो प्रतिशत तक की बढ़त रही। राष्ट्रीय शेयर बाजार में 3,446 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2,259 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।

सोना-चांदी की कीमतों में फिर उछाल

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: सोना और चांदी की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर तेजी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,050 रुपये बढ़कर 2.25 लाख रुपये पर पहुंच गया। वहीं, 24 कैरेट श्रेणी के 10 ग्राम सोने की कीमत 751 रुपये बढ़कर 1.45 लाख रुपये हो गई। इस वर्ष सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में लगभग 12 हजार रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने का मूल्य 1.33 लाख रुपये से अधिक था, जो अब बढ़कर 1.45 लाख रुपये हो गया है। दूसरी ओर, चांदी की कीमत में इस वर्ष अब तक लगभग पांच हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। 31 दिसंबर 2025 को चांदी का भाव 2.30 लाख रुपये प्रति किलोग्राम था, जो अब 2.25 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तथा चांदी ने 3.86 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर भी छुआ था।

अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

पांच रविवार, दूसरे-चौथे शनिवार सहित सात दिन स्थानीय अवकाश के कारण नहीं होगा कामकाज ■ बैंक जाने से पहले अवकाश की सूची जरूर देखें

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अगस्त माह में विभिन्न राज्यों और शहरों में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। इनमें पांच रविवार, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार की नियमित छुट्टियां तथा विभिन्न राज्यों में पड़ने वाले सात स्थानीय अवकाश शामिल हैं। ऐसे में ग्राहकों को बैंक से जुड़े आवश्यक कार्य पहले से योजना बनाकर निपटाने की सलाह दी गई है।

महीने के दौरान 8 अगस्त को दूसरे शनिवार तथा 22 अगस्त को चौथे शनिवार के कारण देशभर के सभी बैंकों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा 2, 9, 16, 23 और 30 अगस्त को रविवार होने के कारण भी सभी बैंक बंद रहेंगे। इन नियमित छुट्टियों के अतिरिक्त अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय पर्वों तथा अन्य घोषित अवकाशों के कारण सात दिन बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। इसलिए ग्राहकों को संबंधित राज्य या शहर में लागू अवकाश की जानकारी पहले से प्राप्त कर बैंक जाने की सलाह दी गई है। हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, स्वचालित धन निकासी मशीन तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से धन का लेनदेन और सामान्य बैंकिंग सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी। इन सेवाओं पर बैंक अवकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंकों ने ग्राहकों से अपील की है कि नकदी निकासी, चेक जमा करने या शाखा से जुड़े अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अवकाश की तिथियों को ध्यान में रखते हुए समय रहते अपनी योजना बना लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जारी मार्गदर्शिका

पेंशन रुकने, जीवन प्रमाण-पत्र और पारिवारिक पेंशन से जुड़ी परेशानियों के लिए बताए गए उपाय

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन परिवार की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार होती है। ऐसे में यदि पेंशन रुक जाए, जीवन प्रमाण-पत्र जमा न हो पाए, पारिवारिक पेंशन शुरू न हो या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा एकीकृत पेंशन योजना से संबंधित कोई समस्या आए, तो सही विभाग से संपर्क कर उसका समाधान किया जा सकता है।

पेंशन रुकने, देरी से मिलने या गलत कटौती होने की स्थिति में सबसे पहले संबंधित बैंक शाखा अथवा पेंशन वितरण कार्यालय में लिखित शिकायत करने की सलाह दी गई है। यदि वहां समाधान नहीं मिलता है, तो केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए पेंशन भुगतान आदेश संख्या, बैंक विवरण तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

जीवन प्रमाण-पत्र अब घर बैठे भी जमा किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल पर जीवन प्रमाण अनुप्रयोग और चेहरे की पहचान सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। यदि यह संभव न हो तो साझा सेवा केंद्र, बैंक या डाकघर की सहायता ली जा सकती है।

पारिवारिक पेंशन शुरू कराने अथवा बैंक बदलने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, आधार, स्थायी खाता संख्या, बैंक खाते का विवरण, पेंशन भुगतान आदेश संख्या तथा नामांकन संबंधी दस्तावेज तैयार रखकर संबंधित विभाग या बैंक में आवेदन करना होगा। देरी होने पर वरिष्ठ नागरिक सहायता सेवा या संबंधित विभाग की सहायता सेवा से संपर्क किया जा सकता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, एकीकृत पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना से जुड़े प्रश्नों के समाधान के लिए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की सहायता सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही कार्यालय और निर्धारित प्रक्रिया अपनाने से अधिकांश पेंशन संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान संभव है।

केनरा बैंक का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 4,856 करोड़ रुपये

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की (अप्रैल-जून) पहली तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है। बैंक का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में दो फीसदी बढ़कर 4,856 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बेंगलुरु स्थित इस बैंक ने पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में 4,752 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। केनरा बैंक ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि 30 जून 2026 को समाप्त पहली तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 39,684 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 38,063 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक की ब्याज से होने वाली आय भी बढ़कर 32,957 करोड़ रुपये हो गई।

नियो समूह ने अनिर्बाण बनर्जी को सह-संस्थापक बनाया

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र की कंपनी नियो समूह ने अनिर्बाण बनर्जी को सह-संस्थापक तथा मुख्य मानव संसाधन एवं परिवर्तन अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि इस नियुक्ति के साथ समूह के शीर्ष नेतृत्व को और मजबूत किया गया है। कंपनी अपने परिसंपत्ति प्रबंधन मंच का विस्तार करने और दीर्घकालिक संस्थागत क्षमताओं में निवेश की दिशा में आगे बढ़ रही है।

नई जिम्मेदारी के तहत अनिर्बाण बनर्जी मानव संसाधन रणनीति, प्रतिभा विकास, नेतृत्व क्षमता निर्माण, संगठनात्मक संरचना, कार्य संस्कृति तथा कंपनी में व्यापक परिवर्तन से जुड़े कार्यों का नेतृत्व करेंगे। मानव संसाधन नेतृत्व के क्षेत्र में उन्हें दो दशक से अधिक का अनुभव है। इससे पहले वह अवेंडस समूह में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इसके पूर्व वह 360 वन, जिसे पहले आईआईएफएल वेल्थ के नाम से जाना जाता था, की नेतृत्व टीम का हिस्सा रहे। वहां उन्होंने कंपनी के शुरुआती वर्षों में मानव संसाधन विभाग की स्थापना और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वर्तमान में नियो समूह सलाहाधीन और प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों के रूप में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये की ग्राहक परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर रहा है। समूह परिवार कार्यालयों, अति धनाढ्य और धनाढ्य ग्राहकों, संस्थागत निवेशकों तथा कंपनियों को परिसंपत्ति प्रबंधन और वैकल्पिक निवेश संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता है। कंपनी की उपस्थिति देशभर में 30 से अधिक स्थानों पर है और इसके साथ लगभग 850 पेशेवर कार्यरत हैं।

नियो समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नितिन जैन ने कहा कि अनिर्बाण बनर्जी ने इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थानों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोगों के विकास और संगठनात्मक परिवर्तन का उनका अनुभव कंपनी को विकास के अगले चरण में नई मजबूती देगा। वहीं, अनिर्बाण बनर्जी ने कहा कि उन्हें नियो में ऐसे संस्थान के निर्माण का अवसर आकर्षित करता है, जहां स्वामित्व की भावना, कार्य संस्कृति और परिवर्तन को कंपनी की विकास यात्रा का आधार माना जाता है। उन्होंने कहा कि वह नेतृत्व टीम के साथ मिलकर समूह के अगले विकास चरण को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं।

परिणाम अधिकारियों से कहा- अधिकार का उपयोग सेवा के लिए करें, लोगों को दफ्तरों के चक्कर न कटवाएं

आयकर विभाग जनता को अनावश्यक परेशान न करे : निर्मला सीतारमण

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के अधिकारियों को आम नागरिकों की सुविधा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अधिकारों का उपयोग लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को अपने कार्य के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।

वित्त मंत्री ने यह बात मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित 13 मंजिला 'आयकर सिंधु' भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि लगभग 1.13 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने इस भवन के निर्माण और विभिन्न

अनुमतियां प्राप्त करने के लिए स्वयं भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि जब इतने अधिकारों से संपन्न अधिकारी भी अनुमतियां लेने के लिए भटकते रहे, तो सहज ही समझा जा सकता है कि एक सामान्य नागरिक को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां उनके अधिकारों की आवश्यकता हो, वहां लोगों को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा या भटकने के लिए मजबूर न किया जाए, बल्कि उनकी सहायता की जाए।

सीतारमण ने सरकारी विभागों की लापरवाही पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नरीमन प्वाइंट की जिस भूमि पर नया भवन बनाया गया है, वह वर्ष 1973 से आयकर विभाग के पास थी, लेकिन समय पर देखरेख नहीं होने के कारण वहां अवैध कब्जे हो गए। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और उनका समय पर उपयोग सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।

सरकारी विभागों के बीच भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया

उन्होंने मुंबई और नवी मुंबई में कार्यरत अधिकारियों के सरकारी आवास की समस्या का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि अनेक अधिकारियों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके कारण उन्हें प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उन्होंने इस विषय पर आवश्यक कदम उठाने तथा विभिन्न सरकारी विभागों के बीच भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से निर्माण कार्य, अनुमतियां, निविदा प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड की उपलब्ध भूमि का उपयोग भी इस दिशा में किया जा सकता है और इस संबंध में वह स्वयं संबंधित मंत्री से चर्चा करेंगी। उन्होंने अधिकारियों से नियमों का पालन करते हुए नागरिकों के प्रति संवेदनशील रहने, ईमानदारी बनाए रखने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कर संग्रह जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ईमानदारी और निष्ठा ही सबसे बड़ा सिद्धांत है।